

development

विकास

विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक रहन-सहन के स्तर, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करने के साथ-साथ अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित होने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार (स्वास्थ्य, पौषाहार, शिक्षा, आवास, औसत आयु, रहन-सहन की दशाएं आदि) तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को सामाजिक विकास कहते हैं।

व्यापक अर्थों में, वांछित लक्ष्यों की ओर बढ़ने का नाम ही विकास है, किन्तु इसमें प्रयुक्त साधनों और यंत्रों का भी उतना ही महत्व है, जितना लक्ष्य का। महात्मा गांधी ने समाज के विकास के संदर्भ में लक्ष्य और साधन दोनों की पवित्रता पर जोर दिया है। विकास में परिवर्तन और उन्नयन दोनों को सम्मिलित किया जाता है, किन्तु परिवर्तन को अर्थपूर्ण और विकास का सौदेश्य होना आवश्यक है। विकास के सर्वस्वीकृत लक्ष्य प्रजातंत्रीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण धर्मनिरपेक्षीकरण, सामाजिक कल्याण, संस्थाओं का निर्माण, सामाजिक मतैक्यता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, और हिंसा रहित तरीकों से विकेन्द्रित समाज की रचना आदि हैं।

समाजशास्त्रियों ने विकास और वृद्धि (ग्रोथ) में भेद किया है। वृद्धि से तात्पर्य सामान्यतः वस्तुओं तथा सेवाओं के परिमाण में होने वाली बढ़ोत्तरी से है, जबकि विकास किसी समाज की क्षमताओं में होने वाले ऐसे गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है जिसके द्वारा कार्यकलापों को अधिक प्रभावशाली ढंग से संगठित किया जाता है। विकास संबंधों के स्वरूपों, नवीन लक्ष्यों, विचारों और पद्धतियों में अभिवर्धन होने वाले संरचनात्मक

परिवर्तन को परिलक्षित करता है। हम बहुधा विकास के साथ सामाजिक न्याय को जोड़ते हैं, इसका तात्पर्य ही यह है कि अन्यों (समृद्ध व्यक्तियों) की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को विकास की रीति-नीतियों और स्वरूपों का अधिक लाभ मिले। सार रूप में, किसी समाज की विद्यमान दशा में कुछ सकारात्मक प्रगति का नाम विकास है। विकास किसे कहा जाये, इसकी धारणा एक समाज से दूसरे समाज में बदलती रहती है।

वस्तुतः सभी सरकारें और नेतागण विकास के प्रति प्रतिबद्ध होने की बात करते हैं। किन्तु नीति निर्माताओं और बुद्धिजिनों में विकास के तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक अवरोधों की सापेक्षिक महत्ता के मुद्दे के बारे में मतभेद हैं; परिणामतः इसे प्राप्त करने की वरीयताओं के बारे में भी इन लोगों में एकमत्यता नहीं है। समाजशास्त्र में इन विषयों पर विचार-विमर्श तो हुआ है, फिर भी मुख्य मुद्दों और लक्ष्यों की सामान्यतः अनदेखी की गई है। सामान्यतः विकास के पश्चिमी मॉडल को हर स्थान पर लागू करने का प्रयास किया गया है। यह मॉडल (आधुनिकीकरण मॉडल) इस बात पर बल देता है कि “पश्चिमी” विश्वासों और संस्थाओं के अपनाये जाने के द्वारा ही दूसरे समाजों का विकास संभव है। इस मॉडल को विकसित करने, प्रचार-प्रसार और लागू करने में अर्थशास्त्रियों की मुख्य भूमिका रही है। मानवशास्त्रियों/समाजशास्त्रियों की सरकार द्वारा प्रवर्तित विकास योजनाओं के प्रति शुरू से ही द्वैधवृत्ति रही है। कुछेक मानवशास्त्रियों/समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार की योजनाओं (सामुदायिक विकास योजना) की कमियों एवं त्रुटियों को भी उजागर किया है, जैसा कि भारत में डा. श्यामाचरण द्वौबे (भारत के बदलते हुए गांव, 1958) के शोध-कार्यों से प्रकट होता है। आरन्झर्बार्न (1964), गुडइनेफ (1963), एम. मीड (1953) और स्पाइसर (1952) जैसे लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों ने सामुदायिक विकास के दिशा-निर्देशों के बारे में सविस्तार लिखा है। यही नहीं, कई मानवशास्त्रियों/समाजशास्त्रियों को इस प्रकार की योजनाओं से सम्बद्ध भी किया गया है। समाजशास्त्रियों ने सामान्यतः विकास के मानवतावादी लक्ष्यों के प्रति तो सहमति प्रकट की है, किन्तु इन योजनाओं में नृजातीय झुकाव के प्रति अपना रोष प्रदर्शित करते हुए कहा है कि तृतीय विश्व के देशों में विकास की ये योजनाएं अमरीकी और पश्चिमी राजनीतिक एवं व्यापारिक हितों में रंगी हुई पाई गई हैं। ऐसे समाजशास्त्रियों जिनका मार्क्सवादी और पराश्रित (आश्रितता) सिद्धान्त वाला परिप्रेक्ष्य रहा है, उन्होंने पूंजीवाद और पश्चिमी विकास की पहल को अल्प विकास के निदान की अपेक्षा उसका कारण माना है।

विकासात्मक योजना के निर्माण में समाजशास्त्रियों ने भारी योगदान किया है। यही कारण है कि आजकल कई शैक्षणिक विभागों में ‘विकास का समाजशास्त्र’ का अध्ययन-अध्यापन किया जाने लगा है, किन्तु कुछेक समाजशास्त्रियों ने इस कदम को मात्र अवसरवादी करार देते हुए इसे सिद्धान्त विहीनता से भरा कार्य बताया है। मोटे रूप में, विकास के तीन प्रमुख प्रतिरूपों (मॉडल्स) का प्रयोग किया गया है: (1) पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल; (2) समाजवादी या मार्क्सवादी मॉडल; तथा (3) मिश्रित मॉडल। रूस, चीन और कुछ अन्य देशों को छोड़ कर पश्चिमी देशों और अमेरिका में पूंजीवादी विकास के मॉडल का प्रयोग किया गया है। मार्क्सवादी मॉडल का प्रयोग साम्यवादी खेमे वाले देशों में किया गया था, किन्तु रूस के पतन के बाद वहाँ भी पूंजीवाद की लहर उत्पन्न हो गई है। भारत में स्वतंत्रता के शुरू के वर्षों में मिश्रित विकास के मॉडल का प्रयोग किया गया था, किन्तु सन् 1990 से अब भारत भी पूंजीवादी (उदारवादी) मॉडल का पेरोकार देश बन चुका है।